राजस्थान सरकार योजना 2025

जनकल्याणकारी व फ्लैगशिप योजनाएं

25 फ्लैगशिप योजनाएं

4th grade |REET | VDO | 1st/2nd Grade | Rajasthan Police

GK Search Engine

BJP सरकार की 25 जनकल्याणकारी व फ्लैगशिप योजनाएं Updated

फ्लैगशिप कार्यक्रम :- ऐसी योजनाएँ व कार्यक्रम जिनकी प्रत्येक माह मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग होती है और हर माह सीएम तक प्रगति रिपोर्ट जाती है।

▶आयोजना विभाग ने प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मासिक सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए है।

▶अप्रैल 2025 में शामिल नई योजनाएँ :- 25 योजनाएँ

▶पूर्व में संचालित योजनाएँ जिन्हें बाहर किया गया :- 33 योजनाएँ

1. NFSA में नए परिवारों को शामिल करना

विभाग- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) में नए परिवारों को शामिल करने की प्रक्रिया राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है।
- इसके लिए, राज्य सरकारें पात्र परिवारों की पहचान करती हैं और उन्हें एनएफएसए के तहत राशन कार्ड जारी करती हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें अयोग्य लाभार्थियों को हटाया जाता है और नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जाता है.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है.

GK Search Engine

2. कुसुम योजना में घटक ए, बी और सी

▶ प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना मार्च 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी

विभाग- ऊर्जा विभाग

> राजस्थान में कुसुम योजना के तीन घटक हैं:

घटक ए:- ग्रिड से जुड़े 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

घटक बी:- 7.5 एचपी क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना।

घटक सी:- ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन ।

> **वित्तीय सहायता**: बैंक के अनुसार किसानों को पंप की लागत का 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है,

3. संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

(विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किये गए विभिन्न कार्य।)

विभाग- ऊर्जा विभाग

- भारत सरकार ने पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्काम्स को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्काम्स को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को मंजूरी दी है।
- इस योजना का 5 वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 में 3,03,758 करोड़ रुपये का परिव्यय है

राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) का आरडीएसएस योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया जाएगा

4. लाडो प्रोत्साहन योजना'

प्रारम्भः- 1 अगस्त, 2024 **विभागः-** महिला एवं बाल विकास विभाग।

प्रदेश में पहले से चल रही 'राजश्री योजना' को अब 'लाडो प्रोत्साहन योजना' में समाहित कर लिया गया

◇ 'राजश्री योजना' में राशि 50 हजार रु. को लाडो प्रोत्साहन में बढ़ाकर 1.50 लाख रु. किया गया है।

◇ खास बात यह है कि परिवार में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को यह लाभ देय है। 2 बालिका की सीमा को हटा दिया गया है।

◇ योजनान्तर्गत गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों को 21 वर्ष की आयु होने तक 7 किश्तों में ₹1.50 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी ताकि उन्हें आर्थिक सम्बल मिल सके।

◇ पहली 6 किश्तें बालिका के माता-पिता के खाते में और 7वीं किश्त बालिका के स्वयं के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

पात्रता :- बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत अस्पताल में हो।

उद्देश्य :- बालिका जन्म को प्रोत्साहन, लिंग भेद को रोकना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।

GK Search Engine

लाडो प्रोत्साहन योजना'

किश्तें :- 7 किश्तों में ₹1.50 लाख

पहली किश्त- जन्म के समय ₹2500,

दूसरी किश्त - एक वर्ष की आयु एवं टीकाकरण पूर्ण होने पर ₹2500

तीसरी किश्त - प्रथम कक्षा में प्रवेश ₹4,000

चौथी किश्त - कक्षा छठी ₹5,000

पाँचवी किश्त- कक्षा 10 में प्रवेश ₹11,000

छठी किश्त 12वीं कक्षा में प्रवेश ₹25,000

7वीं किश्त - स्नातक पूर्ण होने पर एक लाख रुपए होगी।

GK Search Engine

5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

विभाग:- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना और सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना है. इसका मुख्य लक्ष्य हर खेत को पानी उपलब्ध कराना और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है.

प्रारम्भ:- राजस्थान में इस योजना को 2015-16 से लागू किया जा रहा है

- राज्य सरकार विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान कर रही है.
- सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी, डिग्गी, फार्मपौण्ड, जलहोज निर्माण, ग्रीन हाउस, पाली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल एवं ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण।

6. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन

प्रधानमत्री आयुष्मान भारत योजना (स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए)

विभाग:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

▶ आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितम्बर, 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था।

▶ इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।

▶ इसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है

राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना- प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर

7. कर्मभूमि से मात्र भूमि अभियान (वाटर हारवेस्टिंग)

वर्षाजल सहेजने की परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया "कर्मभूमि से मातृभूमि" अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका

शुभारंभ- अक्टूबर 2024

विभाग:- भूजल विभाग

▶ इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण

▶ शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनूं और जयपुर जिलों में कार्य प्राग किए गए

राजस्थान में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान 10 जून 2025 से शुरू

GK Search Engine

8. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] 2 अक्टूबर, 2014 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत उप-मिशनों में से एक है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम): चरण ।। **(2019-2025)**

विभाग:- पंचायती राज विभाग

- ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद, संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के उद्देश्य से एसबीएम-जी चरण 2 का शुभारंभ किया गया, अर्थात 2024-25 तक ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना और सभी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलना।

9. स्वामित्व योजना (सर्वे कर परिवारों को पट्टे बांटना)

विभाग:- पंचायती राज विभाग

▶24 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देना है।

▶भूमि सीमांकन के लिए उन्नत ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करते हुए, यह योजना संपत्ति मुद्रीकरण को बढ़ावा देती है, बैंक ऋण तक पहुँच को आसान बनाती है, संपत्ति विवादों को कम करती है और व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना को बढ़ावा देती है

▶स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को भूमि पट्टे वितरित किये जाएंगे।

GK Search Engine

10. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0

शुरुआत : फरवरी 2024

विभाग : पंचायती राज विभाग

लक्ष्य : 4 वर्षो में राज्य के 20,000 गावों में 5,00,000 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना।

▶इस अभियान के तहत नए एनीकट, खेत तालाब, मिनी परकोलेशन टैंक (MTP), सब सरफेस बैरियर (SSB) का निर्माण एवं पुराने जल संचयन संरचनाओं की मरम्मत आदि का काम किया जाना है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान : ⇒ इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गांव से की गयी थी।

11. अटल ज्ञान केंद्र

विभाग : पंचायती राज विभाग

(3 हजार से अधिक आबदी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं e-library की व्यवस्था)

▶प्रदेश में साढ़े 11 हजार ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे।

▶ प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा की।

▶पहले चरण में प्रदेश की 2 हजार 126 ग्राम पंचायतों पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे

▶अटल ज्ञान केंद्र का भवन बनाने के लिए मिलेंगे 8 लाख रुपए

GK Search Engine

12. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान

विभाग : स्कूल शिक्षा विभाग

▶ माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 29 मार्च को राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत कोटा में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक परिदृश्य को सुदृढ बनाएगा

▶ नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन

▶राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 Sept को कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 'प्रखर राजस्थान 2.0' अभियान और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 'ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली' जैसे नवाचारों का शुभारंभ किया

13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

विभाग : सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) 25 दिसंबर, 2000 को शुरू की गई थी.

▶ इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना और सभी मौसम में सड़कों का निर्माण करना है, खासकर उन इलाकों में जहां 500 (मैदानी क्षेत्रों में) या 250 (पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में) से अधिक आबादी वाले गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं.

▶100% केन्द्र प्रायोजित योजना

14. अटल प्रगति पथ

विभाग : सार्वजनिक निर्माण विभाग

▶राज्य बजट 2025-26 में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा

▶ उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 206.35 करोड़ की लागत के 52 अटल प्रगति पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण।

▶ ग्राम पंचायतों में अटल पथ बनने से ग्रामीणों को जाम व जलभराव सहित अन्य समस्याओं से भी पूरी तरह निजात मिल सकेगी। योजना के तहत सड़कों की चौड़ाई सात मीटर तक होने की वजह से पहले अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। अटल पथों के नेटवर्क की वजह से इलाके के गांव-ढाणियों के लोगों को फायदा मिल सकेगा।

GK Search Engine

15. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

(आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास)

विभाग : स्वायत शासन विभाग

▶**प्रारंभ**- 25 जून 2015

▶ 1 सितंबर 2024 से पाँच वर्षों तक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

▶ प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) एक सरकारी योजना है जो शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए है। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है.

▶योजना में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

16. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

विभाग : स्वायत शासन विभाग

▶स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भकिया गया

▶ स्वच्छ भारत मिशन शहरी (SBM-U) 2.0

▶ योजना प्रारम्भ: अक्टूबर, 2021- 31 Mar 2026

▶ वित्त पोषित : राज्य सरकार : 40% केन्द्रीय सरकार : 60%

▶ स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण व ठोस कचरा प्रबन्धन किया जाता है

GK Search Engine

17.मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

विभाग : स्वायत शासन विभाग

▶ मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का हुआ शुभारंभः 16 दिसम्बर 2024

▶इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल दिया जाएगा।

▶ इस योजना में लाभार्थी को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

18. पीएम विश्वकर्मा योजना

विभाग : उद्योग विभाग

▶17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का शुभारंभ किया।

▶ योजना में ज़िला स्तर पर बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाता है। आवश्यकतानुरूप इन्हें प्रशिक्षण मिलता है

▶18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15 हजार रुपये की टूलकिट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए, 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान

▶ प्रशिक्षण में हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड

▶ हर लाभार्थी को 15 हज़ार रुपए टूल किट के लिये ।

Gk Search Engine

19. मिशन हरियालो राजस्थान

विभाग : वन विभाग

▶ हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई।

▶ राज्य के मुख्यमंत्री ने दूदू ज़िले के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया।

▶ 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरित होकर, राज्य सरकार ने 'मिशन हरियालो राजस्थान' के तहत अगले पाँच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

▶ इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए।

▶राजस्थान सरकार ने "हरियालो राजस्थान अभियान" के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है।

20. जल जीवन मिशन

विभाग : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

▶केंद्रीय बजट 2025-26 में शेष (20%) ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

▶ जल जीवन मिशन (JJM):

▶ जल जीवन मिशन: JJM को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है।

▶ इस योजना के तहत, राजस्थान में साल 2024 तक 92.84 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य था, अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

▶हालाँकि, मिशन को बढ़ाने के बाद, अब राजस्थान को 2028 तक बचे हुए ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें लगभग 47 लाख घरों को पानी के कनेक्शन देने बाकी हैं।

GK Search Engine

21 अमृत योजना

विभाग : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

▶अमृत योजना (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) 25 जून, 2015 को शुरू हुई थी. यह योजना 500 शहरों और कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी.

▶ अमृत योजना 2.0 एक भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित बनाना है. यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी और यह 5 साल के लिए है.

▶ अमृत योजना 2.0 में राजस्थान के 176 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया है.

▶ 2025 में, राजस्थान में अमृत योजना के तहत 5,123 करोड़ रुपये की लागत से 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति परियोजनाएं संचालित की जाएंगी. अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत, 5,830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जल आपूर्ति परियोजनाओं पर चरणबद्ध रूप से कार्य किया जाएगा.

22. पंच गौरव योजना

▶ **विभाग :** आयोजना विभाग

▶ राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसम्बर 2024 में राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में 'पंच-गौरव' कार्यक्रम शुरू किया।

▶इसके तहत हर जिले में एक-एक उपज, वानस्पतिक प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल एवं खेल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

▶ पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये के कार्य करवाने का प्रस्ताव

▶राज्य **सरकार** के कार्यकाल की **पहली वर्षगांठ पर** राज्य के **सभी जिलों** में पंच-मुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए '**पंच-गौरव**' को प्रोत्साहन देने का नवीन **कार्यक्रम शुरू**

GK Search Engine

23. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

विभाग : ग्रामीण विकास विभाग

▶प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।

▶बेघर परिवारों तथा कच्चे एवं टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक सहायता

▶ इस योजना के तहत सामान्य ग्रामीण इलाकों में ₹1,20,000 और दुर्गम इलाकों (पहाड़ी क्षेत्रों) में ₹1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तथा PMAY-G के तहत बनने वाले मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें शौचालय की व्यवस्था भी शामिल है।

24. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त गांव योजना

▶राजस्थान सरकार ने **4 जुलाई 2025** को की शुरुआत की।

विभाग : ग्रामीण विकास विभाग

▶पहले चरण में यह योजना **5,000 गांवों में** गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

▶इसका उद्देश्य गरीबी कम करना और लोगों को छोटे व्यवसायों व नौकरियों के ज़रिए बेहतर आय अर्जित करने में मदद करना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे परिवारों पर केंद्रित है। चुने गए **प्रत्येक परिवार को ₹1 लाख तक की सहायता** दी जाएगी ताकि वे कोई काम या छोटा व्यापार शुरू कर सकें

▶स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी महिलाओं को **₹15,000 प्रति परिवार** की अतिरिक्त सहायता मिलेगी ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। योजना का मकसद है कि लोग दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि स्वावलंबी बनें।

▶जो परिवार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से **₹21,000 का पुरस्कार** दिया जाएगा। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिए उनके सत्यापित बैंक खातों में भेजी जाएगी।

राज्य में लगभग 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं

GK Search Engine

25. नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी

विभाग : ग्रामीण विकास विभाग

नमो ड्रोन दीदी

▶ नमो ड्रोन दीदी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करती है। यह योजना कृषि क्षेत्र में महिलाओं को अधिक योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।

शुरुआत: 11 मार्च 2024 (गाढ़ेपान कोटा से)

- **स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाता है।**
- **ड्रोन उपकरण ऑन की खरीद हेतु 80% या ₹8 लाख तक की सहायता दी जाती है।**

सोलर दीदी

▶ महिलाओं को सौर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्यक्रम गरीबी कम करने के साथ ही ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने

▶बजट 2025 - 26 की घोषणा अनुसार राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 25000 महिलाओं को सोलर दीदी बनाया जाएगा।

▶जबकि सोलर दीदी का नया कैडर बनाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा.

लखपति दीदी

▶राजस्थान में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। Budget 2025-26 **प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है** इसके लिए अगले 5 सालों में हर साल 3 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

▶मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं- महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

GK Search Engine

बैंक सखी

▶ राजस्थान में "बैंक सखी" एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंक की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना है.

कृषि सखी एवं पशु सखी

▶राजस्थान में "कृषि सखी" और "पशु सखी" कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि और पशुपालन में प्रशिक्षित कर उन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने समुदाय की मदद कर सकें। इन सखियों का चयन क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) द्वारा किया जाएगा

▶उन्हें राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की देखरेख में प्रशिक्षित किया जाएगा।

▶यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने और कृषि में उनकी भूमिका को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है

Gk Search Engine

GK Search Engine